नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 166
दि. 21.03.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

खाड़ी में जंग, भारत की रसोई पर असर: महंगाई की नई लहर से आम आदमी परेशान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब भारत के आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा है। यह केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति या सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहने वाला संकट नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम आदमी की थाली, जेब और जीवनशैली पर पड़ रहा है। पेट्रोल से लेकर खाने-पीने की चीजों और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, लगभग हर क्षेत्र में कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो आने वाले महीनों में महंगाई और भी तेज़ी से बढ़ सकती है।

सबसे पहले असर ईंधन की कीमतों पर देखने को मिला है। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 2.09 से 2.35 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum और Indian Oil Corporation जैसी कंपनियां अपने-अपने ब्रांड—स्पीड, पावर और XP95—के नाम से प्रीमियम पेट्रोल बेचती हैं, जो पहले से ही सामान्य पेट्रोल से 10-12 रुपये महंगा होता है। अब इस अतिरिक्त बढ़ोतरी ने खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है, जो हाई-परफॉर्मेंस वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि ने उद्योगों के लिए भी लागत बढ़ा दी है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा।

महंगाई की यह लहर केवल पेट्रोल तक सीमित नहीं रही। ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी अब महंगी हो गई है। Zomato ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हर ऑर्डर पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। रोजाना लाखों ऑर्डर डिलीवर करने वाली इस सेवा की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर शहरी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि महंगाई अब केवल आवश्यक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं के क्षेत्र को भी प्रभावित कर रही है।

खाद्य वस्तुओं की बात करें तो स्थिति और चिंताजनक नजर आती है। भारत

अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, खासकर दालों और खाद्य तेलों के मामले में। शिपिंग लागत बढ़ने और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण अरहर, मसूर और चना दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। भारत हर साल लगभग 70 से 75 लाख टन दालों का आयात करता है, और जब वैश्विक परिवहन महंगा होता है, तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है।

खाने के तेल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। देश में कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत तेल आयात किया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल और रूस-यूक्रेन से सूरजमुखी तेल आयात होता है। युद्ध के कारण इन क्षेत्रों में सप्लाई बाधित होने और लागत बढ़ने से शुरुआती दौर में पांच प्रतिशत तक और लंबे समय में 15 से 25 प्रतिशत तक कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। इसका सीधा असर हर घर की रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि तेल लगभग हर भोजन का अनिवार्य हिस्सा है।

सूखे मेवे और आयातित फलों में तो महंगाई का असर और भी अधिक देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि आने वाले महीनों में इनकी कीमतों में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ईरान और मध्य एशिया से आने वाले पिस्ता, खजूर और काजू, साथ ही अमेरिका और अन्य देशों से आने वाले बादाम और फल महंगे हो सकते हैं। यह न केवल त्योहारों और विशेष अवसरों को प्रभावित करेगा, बल्कि रोजमर्रा के पोषण पर भी असर डालेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में भी महंगाई की आहट सुनाई दे रही है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, एसी और पंखे जैसे उत्पादों के दाम 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। जहाजों के रूट में बदलाव और परिवहन लागत में 20 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि इसका मुख्य कारण है। इससे न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा, बल्कि उद्योगों की उत्पादन लागत भी बढ़ेगी।

निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। स्टील और मशीनरी की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका असर सीधे तौर पर रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे उद्योगों पर पड़ेगा। मकान बनाना महंगा होगा, मशीनरी की लागत बढ़ेगी और छोटे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। भारत का फार्मा सेक्टर कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। जब कच्चा माल महंगा होगा, तो दवाइयों की कीमतों में भी 5 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री की कीमत बढ़ने से दूध, बिस्किट और अन्य रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह महंगाई केवल अस्थायी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक वैश्विक आर्थिक बदलाव का संकेत भी हो सकती है। यदि युद्ध लंबा चलता है, तो सप्लाई चेन में और बाधाएं आएंगी, जिससे कीमतों में और तेजी आ सकती है। ऐसे में सरकार और नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि वे इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

आम आदमी के लिए यह समय सावधानी और समझदारी से खर्च करने का है। जहां एक ओर आय सीमित है, वहीं खर्च बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बजट प्रबंधन, आवश्यक और गैर-आवश्यक खर्चों में संतुलन और बचत की आदत पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।

खाड़ी में चल रही लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक घटनाएं कितनी तेजी से स्थानीय जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आज जो संकट हजारों किलोमीटर दूर दिखाई देता है, वह कुछ ही दिनों में हमारी रसोई, हमारी जेब और हमारे भविष्य पर असर डाल सकता है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यह महंगाई कितनी नियंत्रित हो पाती है और आम लोगों को इससे कितनी राहत मिल पाती है।

चुनावी शंखनाद: बंगाल में 'दीदी' की 10 प्रतिज्ञाएं, महिलाओं युवाओं से लेकर हर परिवार तक को साधने की कोशिश

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच सत्ताधारी All India Trinamool Congress ने अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। राजधानी कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव Abhishek Banerjee समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इस घोषणापत्र का अनावरण किया गया। 'दीदी की 10 प्रतिज्ञाएं' शीर्षक के साथ पेश किए गए इस दस्तावेज में राज्य के हर वर्ग—महिलाओं, युवाओं, किसानों और शहरी-ग्रामीण परिवारों—को ध्यान में रखते हुए बड़े-बड़े वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र का सबसे प्रमुख आकर्षण महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि लोकप्रिय 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 प्रति माह और एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 प्रति माह दिए जाएंगे। इस तरह सालाना यह सहायता क्रमशः 18,000 और 20,400 तक पहुंच जाएगी। यह कदम सीधे तौर पर महिला मतदाताओं

को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य में महिलाओं की भागीदारी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती रही है।

इसी तरह बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए 'बांग्लार युवा-साथी' योजना को जारी रखने का वादा किया गया है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 1500 की सहायता दी जाएगी, जिससे सालाना 18,000 की आर्थिक मदद सुनिश्चित होगी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब रोजगार का मुद्दा राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विषय बना हुआ है और विपक्ष लगातार सरकार पर युवाओं को पर्याप्त अवसर न देने का आरोप लगाता रहा है।

घोषणापत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ा वादा किया गया है। 'दुआरे चिकित्सा' योजना के तहत हर ब्लॉक और शहर में सालाना शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है, जहां अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी महसूस की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में 'बांग्लार शिक्षायतन' योजना के जरिए सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है। इसके तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर कक्षाएं और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हो और अधिक से अधिक छात्र इनकी ओर आकर्षित हों।

कृषि क्षेत्र को लेकर भी घोषणापत्र में बड़ा ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी ने 30,000 करोड़ के विशेष कृषि बजट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, भूमिहीन किसानों को सहायता देना और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को गति देना है। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा घोषणापत्र में हर परिवार को पक्का मकान देने का वादा किया गया है। साथ ही पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी शामिल है। यह दोनों ही वादे बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हैं और सीधे तौर पर आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। राज्य में सात नए जिले बनाने की घोषणा भी की गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का व्यापारिक प्रवेश-द्वार बनाने का भी संकल्प लिया है। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी अपनी बात साझा की और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल वादे करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में भी उनकी सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है और आने वाले समय में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

चंबल में रेत माफिया पर सुप्रीम सख्ती: वन्यजीवों का घर उजड़ा तो अफसर भी नहीं बचेंगे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही अब सीधे कानून के शिकंजे में आएगी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और इसे केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि प्राकृतिक विरासत के साथ गंभीर अपराध माना है। अदालत की यह टिप्पणी उस समय आई है जब लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स में चंबल नदी के किनारों पर अवैध खनन के कारण पर्यावरण और वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए उनसे विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि इस अवैध खनन को तुरंत नहीं रोका गया, तो संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि अब केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने की कोशिश नहीं चलेगी, बल्कि उच्च स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

करीब 5,400 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य देश के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक है। यह अभयारण्य तीन राज्यों—राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश—की सीमाओं को छूता है और यहां कई दुर्लभ तथा लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास है। इनमें घड़ियाल, गंगा की डॉल्फिन और लाल सिर वाले कछुए प्रमुख हैं। ये सभी प्रजातियां पहले से ही संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यदि उनके प्राकृतिक आवास को ही नष्ट कर दिया जाए, तो उनके अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडराना स्वाभाविक है।

अदालत ने इस तथ्य पर गहरी चिंता जताई कि अवैध रेत खनन के चलते नदी के किनारों का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह बदल रहा है। जहां पहले ये क्षेत्र वन्यजीवों के प्रजनन और अंडे देने के लिए सुरक्षित माने जाते थे, वहीं अब वहां भारी मशीनों की आवाज और लगातार हो रही खुदाई ने पूरे वातावरण को असुरक्षित बना दिया है। रेत हटाने से नदी की धारा भी प्रभावित होती है, जिससे जलस्तर और जल प्रवाह में असंतुलन पैदा होता है। इसका सीधा असर न केवल जलीय जीवों पर पड़ता है, बल्कि आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर भी होता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान सरकार के उस निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें अभयारण्य की लगभग 732 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित क्षेत्र से बाहर करने की बात सामने आई है। अदालत ने इस फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह देखा जाएगा कि क्या इस निर्णय से अवैध खनन को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि इस तरह के निर्णय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पाए गए, तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

अदालत ने वन, खनन और जल संसाधन विभागों की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा हो और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी न हो। यह या तो घोर लापरवाही का मामला है या फिर मिलीभगत का। दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में "जिम्मेदारी तय" करने का समय आ गया है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही दो वरिष्ठ वकीलों को न्याय मित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कर अदालत को निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस मामले में गहराई से जांच कर ठोस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है।

चंबल क्षेत्र में अवैध खनन का मुद्दा वर्षों से उठता रहा है, लेकिन अक्सर यह स्थानीय स्तर पर दबा दिया जाता था। हालांकि इस बार मामला सीधे सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। अदालत का यह सख्त रुख न केवल तीन राज्यों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों को अपना पक्ष रखना होगा। इस सुनवाई से यह तय होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और किस स्तर तक जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। फिलहाल, अदालत के इस रुख से यह साफ है कि अब "प्रकृति के साथ अन्याय" करने वालों के खिलाफ कानून पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा।

चुनाव आयुक्त नियुक्ति विवाद में सीजेआई का बड़ा कदम: हितों के टकराव के चलते खुद को किया अलग, अब 7 अप्रैल को नई बेंच करेगी सुनवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका और चुनावी व्यवस्था से जुड़े एक बेहद अहम संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई के दौरान एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उनकी भागीदारी से "हितों के टकराव" (Conflict of Interest) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यदि वे इस मामले की सुनवाई जारी रखते हैं, तो भविष्य में यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने ऐसे विषय पर फैसला दिया, जिसमें उनका व्यक्तिगत या संस्थागत हित जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस पर कोई ऐसी पीठ सुनवाई करे, जिसमें वे न्यायाधीश शामिल न हों जो मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हों।

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि मामले को नई बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। इस पर सहमति जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस मामले की अगली

सुनवाई 7 अप्रैल को एक नई खंडपीठ के सामने की जाए। उन्होंने संकेत दिया कि नई बेंच में ऐसे न्यायाधीश शामिल होंगे, जिनका भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने से कोई सीधा संबंध न हो, ताकि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या हितों के टकराव की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

यह पूरा विवाद "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023" से जुड़ा है, जिसे संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाई गई चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) शामिल होते हैं।

इस कानून को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर भी शामिल हैं, का तर्क है कि मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर करना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। उनका कहना है कि न्यायपालिका की उपस्थिति इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया था कि जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लेकिन बाद में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून में इस व्यवस्था को बदल दिया गया, जिससे यह संवैधानिक बहस और गहरा गई।

केंद्र सरकार ने अदालत में अपने पक्ष में यह दलील दी है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता केवल न्यायिक सदस्य की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक ढांचे में कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए चयन प्रक्रिया में न्यायपालिका की अनिवार्यता नहीं मानी जा सकती।

इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग के बीच संतुलन को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश का इस मामले से खुद को अलग करना न्यायिक मर्यादा और पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका अपने ही मामलों में भी निष्पक्षता को सर्वोपरि मानती है।

अब सभी की नजर 7 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां नई बेंच इस महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगी। यह मामला न केवल चुनाव आयोग की संरचना और स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले समय में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को भी परिभाषित कर सकता है।

ईद तक टला टकराव मगर तनातनी बरकरार

> भारत ने मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़ी आलोचना की। भारत ने इसे 'सैन्य अभियान की आड़ में किया गया नरसंहार' और अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया।

पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान ने बुधवार को ईद-उल-फ़ितर से पहले दुश्मनी में कुछ समय के लिए रोक लगाने का ऐलान किया। इस्लामाबाद और काबुल द्वारा अलग-अलग ऐलान किया गया कि सीज़फ़ायर 18/19 मार्च की आधी रात से 23/24 मार्च की आधी रात तक लागू रहेगा, दोनों पक्षों ने चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन पर मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत फिर से शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा, कि यह फैसला आने वाले इस्लामिक त्योहार को देखते हुए और अच्छी नीयत से लिया गया है। तरार बोले, 'आने वाले इस्लामिक त्योहार ईद-उल- फ़ितर को देखते हुए, 'भाई इस्लामिक देशों' की गुज़ारिश पर 'ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक' के बीच कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया है।'

पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने कहा कि यह रोक 'अच्छी नीयत और इस्लामिक नियमों के हिसाब से' लगाई जा रही है, लेकिन यह साफ किया कि यह समझौता शर्तों पर है। बयान में चेतावनी दी गई, 'पाकिस्तान के अंदर किसी भी क्रॉस-बॉर्डर हमले, ड्रोन हमले या आतंकवादी घटना की स्थिति में, 'ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक' नई तेज़ी के साथ शुरू होगा।'

दूसरी तरफ, अफगान तालिबान शासन ने भी 'डिफेंसिव ऑपरेशन (राद-उल जुल्म)' कहे जाने वाले अभियान पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की पुष्टि की है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि ईद-उल-फितर के मौके पर हम भी ख़ामोश रहेंगे। मुजाहिद ने कहा, 'इस्लामिक अमीरात ऑफ़ अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स, ईद-उल-फितर के मौके पर 'डिफेंसिव ऑपरेशन्स (रद-उल-जुल्म)' को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने की घोषणा करती हैं।' उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की और कतर की 'अच्छी नीयत और कंस्ट्रक्टिव कोशिशों' की तारीफ़ की, साथ ही दोहराया कि 'किसी भी खतरे की हालत में, इस्लामिक अमीरात मज़बूती से जवाब देगा।'

हालांकि दोनों पक्षों ने इसे सशर्त अस्थाई रोक बताया है, फिर भी जानकार सावधानी से देख रहे हैं, कि क्या इस पहल से बड़े पैमाने पर बातचीत का रास्ता बन सकता है? यह कदम पाकिस्तान के काबुल में नए एयरस्ट्राइक शुरू करने के दो दिन बाद आया, जिसमें करीब 400 से अधिक सिविलियन मारे गए हैं। एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, और कहा कि काबुल में हालिया हमले का मुख्य टारगेट एक डिपो था, जिसमें अफगान तालिबान का गोला-बारूद, हथियार और ड्रोन थे।

डीजी आईएसपीआर ने कहा कि यह ऑपरेशन अफगान तालिबान द्वारा पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर किए गए 53 हमलों के जवाब में किया गया था। उन्होंने आम लोगों के मारे जाने की खबरों को प्रोपेगैंडा बताते हुए उसे खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि तालिबान लड़ाके अक्सर यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, और इसके बजाय आम लोगों के कपड़े पहनते हैं, और तालिबान सुसाइड हमलों के लिए ड्रग एडिक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पकिस्तान का झूठ एक्सपोज़ करने के वास्ते अफ़ग़ानिस्तान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल की प्रभारी वेरोनिका बोस्कोविक पोहार ने कज़ाकिस्तान के राजदूत और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काबुल में उस नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया, जिसे मंगलवार की सुबह पाकिस्तान के सैन्य शासन द्वारा निशाना बनाया गया था।

डीजी आईएसपीआर ने आरोप लगाया, कि हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया, उन्हें भारत सप्लाई कर रहा था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान का अफगान लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, जो खुद आतंकवादियों के बंधक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और दावा किया कि आतंकवादी गतिविधियों के पीछे भारत का हाथ है। चीन खामोशी से दोनों तरफ के हमले देख रहा है। अफ़ग़ानिस्तान को सैन्य मदद चीन से भी मिली है। वर्ष 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से, चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को रोकने के लिए, अफ़ग़ानिस्तान को मिलिट्री ट्रेनिंग और हार्डवेयर प्रदान किए हैं। लेकिन रावलपिंडी की हिम्मत नहीं, कि वह चीन के ख़िलाफ़ चूं भी बोले।

त्रालाई मस्जिद हमले का ज़िक्र करते हुए डीजी आईएसपीआर ने कहा कि इसमें बेगुनाह लोग मारे गए। हमलावर अफगानिस्तान से आया था, जहां उसने ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने वाना कैडेट कॉलेज पर हुए हमले का भी ज़िक्र किया, और कहा कि मारे गए सभी पांच हमलावर अफगान नागरिक थे। उन्होंने कहा कि पुलिस, आम लोगों, और मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। इन आतंकी संगठनों के सरगना अफ़ग़ानिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने अपनी नवीनतम सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल-हक नाम दिया। इसका अर्थ 'सत्य के लिए क्रोध' या 'न्याय के लिए रोष' समझा जाता है। पिछले दो दशकों में, पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अधिकांश अभियानों को धार्मिक नाम दिए गए हैं। धार्मिक एंगल पाकिस्तानी अवाम से राजनीतिक फायदे के वास्ते भी है।

15 जून, 2014 को, अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगे एक कबायली क्षेत्र, उत्तरी वज़ीरिस्तान में, सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ़ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू किया था। जिसका सामूहिक अर्थ है 'सत्य की तलवार का प्रहार'। फरवरी 2017 में, पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए चारों प्रांतों में राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान चलाया और ऑपरेशन 'रद-उल-फसाद' के तहत कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिसका अर्थ है 'अव्यवस्था और आतंकवाद का उन्मूलन'। एकाध बार अंग्रेजी नाम भी पाकिस्तान ने रखे, मसलन, 2019 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान, पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमलों के जवाब में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट (त्वरित प्रतिक्रिया) की घोषणा की, जिसमें भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया गया था। पाकिस्तान ने 1990 के दशक की शुरुआत में अफ़गान तालिबान बनाने में मदद की थी। वर्ष 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के दौरान कई तालिबान लीडर पाकिस्तान में छिपे थे। तब अमेरिकी विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तानी नेताओं से कहा था, 'आप अपने घर के पीछे सांप नहीं पाल सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ़ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे।'

भारत ने मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़ी आलोचना की। भारत ने इसे 'सैन्य अभियान की आड़ में किया गया नरसंहार' और अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया। पाकिस्तान यदि भारत पर हमले के लिए चीनी हथियार का सहारा ले तो सही। अफ़ग़ानिस्तान, भारत से सैन्य मदद ले, तो ग़लत। भारत यदि तालिबान से सैन्य सहयोग समझौता कर चुका है, तो उसे खुलकर मदद करने में कोई बुराई नहीं है। दुश्मन का दुश्मन, दोस्त होता है!

संपादकीय

चंडीगढ़ तक पहुंची गैंगवार की तपिश

सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर शहर चंडीगढ़ कुछ समय पहले तक, अपनी चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिये मशहूर रहा है। इस शहर को लंबे समय तक हिंसा व अपराधों से सुरक्षित माना जाता रहा है। लेकिन विडंबना है कि अब यह तेजी से असुरक्षित होता जा रहा है। पिछले दिनों चंडीगढ़ का पॉश इलाका माने जाने वाले सेक्टर नौ में एक युवा प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हुई चौंकाने वाली हत्या ने शहर की शांति व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की सावधानीपूर्वक बनायी गई इस केंद्रशासित प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। निस्संदेह, इस केंद्र शासित प्रदेश के सबसे समृद्ध और सुरक्षित इलाकों में से एक सेक्टर में, इस तरह की सरेआम निर्मम हत्या होना न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह बेहद गंभीर अपराध बढ़ने का संकेत भी देता है। शुरुआती रिपोर्टों में इस अपराध को गैंगस्टरों की आपसी दुश्मनी से जोड़ कर देखा जा रहा है। जिसमें लकी पटियाला और बबीहा गैंग जैसे नामों का जिक्र सामने आया है। यह हत्याकांड एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है कि अब संगठित अपराध उन शहरी केंद्रों में लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्हें कभी इस तरह की गैंगवार से अछूता समझा जाता था। माना जाता रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस यथाशीघ्र अपराध की जड़ तक पहुंचकर अपराधियों पर शिंकजा कसने में सफल रहती है। यह चौंकाने वाली बात है कि हाल के वर्षों में पंजाब में गैंगवार में होने वाली हिंसा और जबरन वसूली के रैकेट में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या है। निस्संदेह, सेक्टर नौ में दिनदहाड़े हुई हत्या से साल 2017 में हुए आकांक्षा सेन हत्याकांड की टीस एक बार फिर उभर आई। यह भी एक ऐसा ही हाई-प्रोफाइल मामला था। जिसमें न्याय मिलने में लगातार हुई देरी के कारण आज भी लोगों के मन में गहरी कसक व्याप्त है। निस्संदेह, दोनों ही हत्याकांडों से जुड़ी समानताएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। मसलन, अपराध सार्वजनिक रूप से हुए हैं। जिससे अपराध को रोकने की पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें एक सवाल जवाबदेही का भी है।

वास्तव में इस तरह सरेआम दिन दहाड़े होने वाले अपराध सार्वजनिक विमर्श में कई संवेदनशील सवालों को जन्म देते हैं। इस घटना से जुड़ा सबसे चिंताजनक पहलू है हत्याकांड में शामिल रहे अपराधियों का दुस्साहस। निर्विवाद रूप से सार्वजनिक स्थल के बाहर दिन-दहाड़े की गई हत्या बताती है कि ये अपराधियों में कानून-व्यवस्था के प्रति डर समाप्त होने का संकेत है। जिसके परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन की निवारक क्षमता कमजोर हो जाती है। निस्संदेह, इस तरह की घटनाओं को लेकर खुफिया जानकारी जुटाने, पुलिस समन्वय और ऐसे हमलों को रोकने की क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। कोई शक नहीं कि चंडीगढ़ को अब किसी भी तरह की लापरवाही का शिकार बनने नहीं दिया जा सकता। प्रशासन को प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग के बजाय सक्रिय और खुफिया जानकारी आधारित रणनीति अपनानी होगी। निश्चित रूप से ऐसे अपराधों पर तभी अंकुश लगाना संभव हो पाएगा, जब पुलिस का लक्ष्य आपराधिक गिरोहों, उनकी आर्थिक मदद करने वालों तथा उनके सहयोगियों के गठजोड़ को नेस्तनाबूद करना होगा। इसमें दो राय नहीं कि आपराधिक मामलों में तुरंत जांच, पुलिस की प्रत्यक्ष उपस्थिति और समय पर न्याय मिलने से न केवल जनता का विश्वास बहाल होगा, बल्कि शहरों को आने वाले समय में ऐसे गैंगवार से जुड़ी हिंसा से भी बचाया जा सकेगा। निस्संदेह, नई तकनीक और इंटरनेट आधारित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये हाइटैक पुलिस की जरूरत होगी। नई तकनीक जहां अपराधियों का हथियार बनती है, वहीं उन पर शिकंजा कसने में मददगार हो सकती है। बशर्ते इन संसाधनों का उपयोग सावधानी व तत्परता से किया जाए। तब अपराधियों की गैंगवार पर नकेल डालने में खुफिया जानकारी और आधुनिक तकनीक खासी मददगार हो सकती हैं। सिटी ब्यूटीफुल में कानून व्यवस्था की खूबसूरती बचाने के लिये जरूरी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। निस्संदेह, यही वक्त की मांग भी है।

प्रेरणा

संघर्ष, जिज्ञासा और सफलता की अद्भुत कहानी

जीवन की राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कई बार परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान को अपने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते। यही आग उन्हें साधारण से असाधारण बना देती है। सोवियत रूस की धरती पर जन्मे एक ऐसे ही बालक की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, जिसने अभावों के बीच भी अपने ज्ञान की प्यास को जिंदा रखा और अंततः दुनिया के महान साहित्यकारों में अपनी पहचान बनाई। यही बालक आगे चलकर मैक्सिम गोर्की के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

उसका बचपन किसी भी दृष्टि से आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने माता-पिता को खो दिया, जिससे जीवन का आधार ही डगमगा गया। उसके सिर पर जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ आ गया, जिसे उठाना किसी भी बच्चे के लिए बेहद कठिन होता है। उसकी बूढ़ी दादी ही उसका एकमात्र सहारा थीं, लेकिन उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। जहां एक ओर उसके हमउम्र बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वह जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना कर रहा था।

रोजी-रोटी की तलाश में उसे एक कबाड़ी की दुकान पर काम करना पड़ा। यह काम न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाला था, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। दिनभर पुराने और बेकार समझे जाने वाले सामानों के बीच काम करते हुए कोई भी व्यक्ति निराश हो सकता था, लेकिन इस बालक ने इन्हीं परिस्थितियों में अवसर तलाश लिया। कबाड़ी की दुकान पर अक्सर रद्दी में पुरानी किताबें भी आती थीं, जिन्हें लोग बेकार समझकर बेच देते थे। लेकिन वही किताबें उसके लिए ज्ञान का खजाना बन गईं।

वह काम के बीच-बीच में उन किताबों को पढ़ता रहता। हर पन्ना उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देता। यह पढ़ाई किसी नियम या पाठ्यक्रम के तहत नहीं थी, बल्कि यह उसकी अपनी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा का परिणाम थी। जब भी उसे कोई बात समझ में नहीं आती, तो वह बिना झिझक के दूसरों से पूछता। कभी वह कबाड़ी से सवाल करता, तो कभी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से। उसकी यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वह हर सवाल का जवाब पाने के लिए प्रयास करता और तब तक संतुष्ट नहीं होता, जब तक उसकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए।

धीरे-धीरे यह आदत उसकी ताकत बन गई। वह केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने विचारों को शब्दों में ढालना भी शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभवों, अपने आसपास के समाज और अपने भीतर चल रहे विचारों को लेखों के रूप में लिखना शुरू किया। शुरुआत में यह केवल एक प्रयोग था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने लेख स्थानीय अखबारों को भेजने शुरू कर दिए। यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि बिना किसी औपचारिक शिक्षा और पहचान के अपने विचारों को दुनिया के सामने रखना आसान नहीं होता।

कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसके लेख अखबारों में प्रकाशित होने लगे। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। जब उसने अपने नाम के साथ अपने विचारों को छपा हुआ देखा, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। अखबारों के संपादकों ने भी उसकी लेखनी की सराहना की और उसे आगे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। यह प्रोत्साहन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि वह भी कुछ बड़ा कर सकता है।

समय के साथ उसकी लेखनी में और निखार आता गया। उसने समाज के उन पहलुओं को अपने लेखन का विषय बनाया, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। गरीबों, मजदूरों और संघर्षरत लोगों की जिंदगी को उसने इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया कि पाठक उसके शब्दों से खुद को जोड़ने लगे। उसकी रचनाओं में सच्चाई और संवेदनशीलता की झलक साफ दिखाई देती थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी।

आखिरकार वही बालक, जिसने कभी कबाड़ी की दुकान में रद्दी के ढेर से किताबें उठाकर पढ़ना शुरू किया था, एक महान साहित्यकार बन गया। मैक्सिम गोर्की ने साहित्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। उनकी प्रसिद्ध कृति मां आज भी विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है, जिसमें संघर्ष, समानता और परिवर्तन का संदेश छिपा हुआ है।

उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि इंसान के भीतर सीखने की ललक और आगे बढ़ने का जुनून हो, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने कभी अपनी गरीबी या अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज संसाधन नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और मेहनत है।

आज के समय में जब लोग छोटी-छोटी मुश्किलों से घबराकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, तब मैक्सिम गोर्की की यह कहानी एक प्रेरणा के रूप में सामने आती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि असली शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन के हर अनुभव से मिलती है। जो व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही आगे बढ़ता है और वही अपनी पहचान बनाता है। अंततः यह कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हमारे भीतर कुछ करने का जज्बा हो, तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। संघर्ष की आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, और यही सच्चाई इस प्रेरक गाथा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

China के मुकाबले India की रक्षा तैयारी कितनी मजबूत है? संसाधन और ताकत के मामले में कौन-सा देश आगे है?

एशिया की भू राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। एक तरफ विस्तारवादी मंशा से आगे बढ़ता चीन है और दूसरी तरफ तेजी से आत्मनिर्भर और आक्रामक रणनीति अपनाता भारत है। सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बल्कि सवाल यह है कि अगर टकराव हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। तथ्य बताते हैं कि चीन अभी भी संसाधनों और संख्या के मामले में आगे है, लेकिन भारत ने पिछले एक दशक में जो रणनीतिक बदलाव किए हैं, उन्होंने इस अंतर को तेजी से कम किया है। सबसे पहले सैन्य संख्या की बात करें तो चीन के पास लगभग बीस लाख सक्रिय सैनिक हैं जबकि भारत के पास करीब चौदह से पंद्रह लाख के बीच सक्रिय सेना है। पहली नजर में यह अंतर बड़ा लगता है, लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। भारत के पास अर्धसैनिक बलों का विशाल ढांचा है जो युद्ध की स्थिति में बड़ी ताकत बन सकता है।

हथियारों और तकनीक की बात करें तो वायु शक्ति के मामले में तस्वीर साफ तौर पर चीन के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है। कुल सैन्य विमान बेड़े में चीन के पास लगभग 3300 से अधिक विमान हैं, जबकि भारत के पास करीब 2229 विमान हैं। यानी संख्या के लिहाज से चीन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। अगर केवल लड़ाकू विमानों की बात करें तो यह अंतर और भी चौड़ा हो जाता है। चीन के पास करीब 2000 से 2100 लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारत के पास लगभग 550 से 600 के बीच फाइटर जेट हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि सीधे हवाई टकराव की स्थिति में चीन की संख्या आधारित ताकत भारी पड़ सकती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। भारत की वायुसेना केवल संख्या पर नहीं, बल्कि संतुलित संरचना, मल्टी रोल क्षमता और रणनीतिक तैनाती पर आधारित है, जो उसे हर हालात में जवाब देने लायक बनाती है।

इसके अलावा यह भी तथ्य अहम है कि भारत इस अंतर को तेजी से कम करने की दिशा में आक्रामक कदम उठा चुका है। भारत ने फ्रांस के साथ बड़े स्तर पर रक्षा करार करते हुए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, जो विमानवाहक पोतों पर तैनात होंगे और समुद्री युद्ध क्षमता को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही भारत 114 नए मल्टी रोल राफेल लड़ाकू विमानों के बड़े सौदे की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जो वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इतना ही नहीं, फ्रांस के साथ संयुक्त उत्पादन, हेलिकॉप्टर निर्माण और मिसाइल सिस्टम के सह उत्पादन जैसे समझौते भी किए जा रहे हैं, जिससे भारत न केवल अपनी वायु शक्ति बढ़ा रहा है बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वायु शक्ति बढ़ाने के लिए भारत कई अन्य देशों से भी खरीद के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का युद्ध अनुभव चीन से कहीं अधिक व्यावहारिक है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की बात करें तो भारतीय सेना का अनुभव लद्दाख और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में चीन से कहीं आगे है। यह वह मोर्चा है जहां आंकड़े नहीं बल्कि जमीनी हकीकत जीत तय करती है।

इसके अलावा, जमीनी युद्ध की स्थिति में हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक किला बन जाता है। चीन की भारी सेना और उपकरण इस इलाके में उतने प्रभावी नहीं रह जाते जितने खुले मैदान में होते हैं। भारतीय सेना ने दशकों तक इन परिस्थितियों में खुद को ढाला है, जबकि चीन को इस तरह की चुनौतियों का सीमित अनुभव है।

वहीं तोपखाने और तैनाती की बात करें तो भारत की स्थिति कई मामलों में मजबूत है। ऊंचाई पर तेजी से हथियार पहुंचाने और उन्हें संचालित करने की क्षमता भारत की बड़ी ताकत है।

नौसेना के क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग है। चीन की नौसेना आकार में बड़ी है, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक बढ़त देती है। हिंद महासागर में भारत का प्रभाव चीन के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। भारत के पास विमानवाहक पोत हैं और समुद्री मार्गों पर उसकी पकड़ मजबूत है। युद्ध की स्थिति में यह क्षेत्र चीन की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है।

अब बात आती है आधुनिक युद्ध की, जहां असली खेल साइबर और अंतरिक्ष में हो रहा है। इस क्षेत्र में चीन ने तेजी से बढ़त बनाई है। साइबर हमले, उपग्रह तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में चीन आगे है। भारत ने इस दिशा में कदम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन अभी काफी दूरी तय करनी बाकी है। यही वह क्षेत्र है जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा तय करेगा।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से यह मुकाबला केवल दो देशों के बीच नहीं है। यह पूरे एशिया में शक्ति संतुलन की लड़ाई है। भारत अब केवल सीमा की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और वैश्विक साझेदारियां इस दिशा में साफ संकेत देती हैं।

अभियान

नाम जप की परंपरा और रहस्य: 'कृष्ण-कृष्ण' व 'शिव-शिव' उच्चारण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं

भारतीय सनातन परंपरा में नाम जप को सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली साधना माना गया है। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक सूक्ष्म संवाद है, जिसमें शब्दों के माध्यम से भक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बड़े-बड़े यज्ञ, तप या कठिन साधनाएं नहीं कर सकता, तो वह केवल भगवान के नाम का जप करके भी वही फल प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय समाज में अभिवादन से लेकर दैनिक जीवन तक, ईश्वर के नाम का उच्चारण एक सामान्य और पवित्र परंपरा के रूप में स्थापित है। 'राम-राम', 'राधे-राधे', 'जय श्रीकृष्ण' और 'हर-हर महादेव' जैसे संबोधन न केवल श्रद्धा के प्रतीक हैं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की झलक भी देते हैं।

इसी परंपरा के बीच एक रोचक प्रश्न अक्सर उठता है कि जब 'राम-राम' या 'राधे-राधे' कहना सामान्य है, तो 'कृष्ण-कृष्ण' या 'शिव-शिव' का उच्चारण क्यों कम सुनने को मिलता है। क्या इसके पीछे कोई धार्मिक निषेध है, या फिर यह केवल परंपरागत आस्था का हिस्सा है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कारण में सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, दर्शन, भक्ति और ज्योतिषीय मान्यताओं का एक सम्मिलित परिणाम है।

श्रीकृष्ण के संदर्भ में यह माना जाता है कि उनका नाम हमेशा राधा के साथ जुड़ा हुआ है। वैष्णव परंपरा में राधा और कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यही कारण है कि 'राधे-कृष्ण' या 'राधे-राधे' जैसे संबोधन अधिक प्रचलित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रीकृष्ण की कृपा तभी प्राप्त होती है, जब साधक पर राधा की कृपा होती है। यह विचार भक्ति आंदोलन के कई संतों और ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, जहां राधा को भक्ति की पराकाष्ठा और प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना गया है।

कहा जाता है कि स्वयं श्रीकृष्ण ने राधा को यह वरदान दिया था कि उनका नाम हमेशा पहले लिया जाएगा। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह उस गूढ़ सत्य को दर्शाता है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और समर्पण से होकर गुजरता है। इसलिए जब कोई 'राधे-राधे' कहता है, तो वह केवल राधा का ही नहीं, बल्कि कृष्ण का भी स्मरण कर रहा होता है।

दूसरी ओर, शिव के नाम के उच्चारण को लेकर भी कुछ विशेष मान्यताएं प्रचलित हैं। सामान्यतः लोग 'हर-हर महादेव' या 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं, लेकिन 'शिव-शिव' का उच्चारण अपेक्षाकृत कम किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही प्रकार के कारण बताए जाते हैं।

धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो शिव को पूर्ण और निराकार माना जाता है। वे सृष्टि के संहारक होने के साथ-साथ करुणा और वैराग्य के प्रतीक भी हैं। उनका स्वरूप इतना व्यापक और गूढ़ है कि उन्हें साधारण शब्दों में बांधना कठिन माना जाता है। 'हर-हर महादेव' का अर्थ होता है कि हर जीव में महादेव का वास है, जो एक सार्वभौमिक और समावेशी विचार को व्यक्त करता है। वहीं 'ॐ नमः शिवाय' एक पंचाक्षरी मंत्र है, जिसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी 'शिव-शिव' के उच्चारण को लेकर कुछ विशेष तर्क दिए जाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, 'श' और 'व' अक्षरों के संख्यात्मक मान को जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, वह पंच तत्वों और पंच भूतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। पंच तत्व, अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मानव शरीर के मूल आधार हैं। वहीं पंच भूत उन सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रकृति में व्याप्त हैं।

यह माना जाता है कि जब 'शिव-शिव' का उच्चारण बार-बार किया जाता है, तो यह इन ऊर्जाओं को सक्रिय कर सकता है। चूंकि मानव शरीर स्वयं पंच तत्वों से बना है, इसलिए वह इन ऊर्जाओं को एक सीमा तक सहन कर सकता है। लेकिन यदि यह ऊर्जा असंतुलित हो जाए, तो यह मानसिक या शारीरिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से 'शिव-शिव' के बजाय 'हर-हर महादेव' या 'ॐ नमः शिवाय' जैसे मंत्रों को अधिक सुरक्षित और संतुलित माना गया है।

हालांकि, यह समझना भी आवश्यक है कि ये सभी मान्यताएं मुख्यतः आस्था और परंपरा पर आधारित हैं। हिंदू धर्म में किसी भी नाम के उच्चारण पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से 'कृष्ण-कृष्ण' या 'शिव-शिव' का जाप करता है, तो उसकी भक्ति निश्चित रूप से स्वीकार की जाती है। धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण हैं, न कि केवल शब्दों का चयन।

नाम जप का वास्तविक उद्देश्य मन को एकाग्र करना और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है। जब व्यक्ति बार-बार किसी नाम का उच्चारण करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे उस नाम के अर्थ और भाव में डूबने लगता है। यही प्रक्रिया ध्यान और साधना का आधार बनती है। इस दृष्टि से देखा जाए, तो 'राम-राम', 'राधे-राधे' या 'हर-हर महादेव' जैसे संबोधन केवल शब्द नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव हैं।

समय के साथ ये परंपराएं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी स्थापित हो गई हैं। लोग इन्हें केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि आपसी संवाद और पहचान के रूप में भी अपनाते हैं। उत्तर भारत में 'राम-राम' कहना एक सामान्य अभिवादन बन चुका है, जबकि ब्रज क्षेत्र में 'राधे-राधे' का विशेष महत्व है। इसी प्रकार, शिव भक्त 'हर-हर महादेव' का उद्घोष करके अपनी आस्था प्रकट करते हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि 'कृष्ण-कृष्ण' और 'शिव-शिव' के उच्चारण को लेकर जो मान्यताएं प्रचलित हैं, वे धर्म, दर्शन और ज्योतिष के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम हैं। यह किसी कठोर नियम या निषेध का विषय नहीं है, बल्कि यह उस गूढ़ समझ का हिस्सा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव और परंपरा के माध्यम से विकसित किया है। इन मान्यताओं का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि साधना संतुलित और प्रभावशाली बनी रहे।

भक्ति का मार्ग हमेशा सरल और खुला होता है। इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक भावना पर आधारित होता है। इसलिए चाहे कोई 'राधे-राधे' कहे, 'जय श्रीकृष्ण' बोले या 'हर-हर महादेव' का उद्घोष करे, यदि उसके मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण है, तो वह निश्चित रूप से ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे अन्य परंपराओं से अलग और विशिष्ट बनाती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत केन्द्र व राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण एमओयू

सरकार राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक नल से जल पहुँचाने के लिए कटिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- सरकार द्वारा किया गया यह एमओयू राज्य के पेयजल प्रबंधन एवं ग्रामीण जनजीवन के गुणात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
- राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की हर योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में शुक्रवार को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है।

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल तथा राज्य के जलापूर्ति मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती-दूरदराजी क्षेत्रों सहित हर कोने तक पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने जोड़ा कि सरकार द्वारा किया गया यह एमओयू राज्य के पेयजल प्रबंधन एवं ग्रामीण जनजीवन के गुणात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री पटेल ने आगे कहा कि राज्य सरकार केन्द्र की हर योजना का प्राथमिकता के आधार पर सफल क्रियान्वयन करती है। जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत हुआ यह एमओयू राज्य के ग्रामीण विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। हर घर में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुँचाने का संकल्प अब और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा।

जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त, 2019 को 'हर घर जल' के संकल्प के साथ की गई थी, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पीने का पानी पहुँचाने का उद्देश्य रखा गया था। गुजरात ने यह लक्ष्य अक्टूबर, 2022 तक सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है।

अब जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत 2028 तक जलापूर्ति व्यवस्था का अधिक सुदृढ़ीकरण, नियमितता तथा सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस एमओयू द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी तथा पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

इस एमओयू के अनुसार राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर-निर्बाध एवं गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा 'हर घर जल' प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयास अधिक वेगवान बनेंगे।

एमओयू अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं को समय पर तथा गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को सौंपने, संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) सुनिश्चित करने, ग्रामीण स्तर पर विलेज वॉटर एंड सेनिटेशन समिति (वीडब्लूएससी) द्वारा जल प्रबंधन का संचालन करने, जल स्रोतों की दीर्घकालीन सुरक्षा करने और सस्टेनेबिलिटी पर बल देने जैसे विषय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त; डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए 'सुजलम भारत' तथा 'पीएम गति शक्ति' जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण, वित्तीय अनुशासन, 'नल से जल मित्र' जैसी पहलों के माध्यम से मानव संसाधन विकास एवं जल संरक्षण के लिए 'जल उत्सव' जैसे अभियान भी इस मिशन का अभिन्न हिस्सा रहेंगे।

इस एमओयू के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारियाँ भी स्पष्ट की गई हैं। केन्द्र सरकार मार्गदर्शन, फंडिंग तथा मॉनिटरिंग करेगी; जबकि राज्य सरकार क्रियान्वयन, नीति सुधार तथा टेक्निकल सपोर्ट की जिम्मेदारी निभाएगी।

इस अवसर पर केन्द्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सहभागी हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम में जलापूर्ति विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती शाहमीना हुसैन, जलापूर्ति विभाग के मुख्य अभियंता श्री नीरव सोलंकी, सुश्री धरा व्यास तथा श्री भाविक राठौड़ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने चेटीचंड के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएँ देते हुए भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा को प्रस्थान कराया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- सिंधी समाज ने साहस, परिश्रम तथा पुरुषार्थ से व्यापार-वाणिज्य सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है
- गुजरात को अपनी मातृभूमि व कर्मभूमि बनाने वाले सिंधी समाज ने अपनी भाषा एवं पहचान बनाए रखते हुए दूध में चीनी की भाँति घुलकर राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दिया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को सिंधी समाज के भाइयों-बहनों को चेटीचंड के पवित्र त्योहार की शुभकामनाएँ देते हुए भगवान झूलेलाल की शोभायात्रा को प्रस्थान कराया। अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) तथा चेटीचंड महोत्सव समिति द्वारा नरोडा पाटिया क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि चेटीचंड दरियादेव की आराधना का पवित्र त्योहार है और इसके साथ आज चैत्री नवरात्रि की उपासना का भी पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज साहस, परिश्रम तथा पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है और इस समाज ने व्यापार-वाणिज्य सहित अनेक क्षेत्रों में परचम लहराया है।

श्री पटेल ने आगे कहा कि सिंध से आकर गुजरात को अपनी मातृभूमि व कर्मभूमि बनाने वाले सिंधी समाज ने अपनी भाषा एवं पहचान बनाए रखते हुए गुजरात की संस्कृति में दूध में चीनी की भाँति घुलकर राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दिया है। समाज की यह भावना 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के मंत्र को साकार करती है।

उन्होंने जोड़ा कि नई पीढ़ी अपनी परंपरा तथा विरासत के साथ जुड़े; इसके लिए ऐसे धार्मिक एवं सामूहिक आयोजन महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपील की कि सिंधी समाज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'कैच द रेन', 'एक पेड़ माँ के नाम' तथा 'स्वच्छ भारत' जैसे अभियानों में सक्रिय सहभागी बने।

इस अवसर पर विधायक डॉ. पायलबेन कुकरानी ने स्वागत संबोधन में कहा कि धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सिंधी समाज ने अपने वतन सिंध को छोड़कर भारत को अपना घर बनाया और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह में शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा व श्री हसमुखभाई पटेल, विधायक श्रीमती कंचनबेन रादडिया, पूर्व मंत्री श्री मायाबेन कोडनानी, पूर्व विधायक श्री निर्मलाबेन वाधवानी, सिंधी समाज के संत-महंत तथा भाई-बहन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सूरत आरटीओ के फैसले से दोपहिया वाहन शोरूमों में आक्रोश, उप-डीलरों को भारी नुकसान

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। वर्तमान में चैत्र के पवित्र महीने में नए वाहनों की खरीद हो रही है, जिसमें दोपहिया वाहन मुख्य रूप से मध्यम वर्ग द्वारा खरीदे जाते हैं। ऐसे में सूरत आरटीओ के शोरूम में बहुउद्देशीय (प्रत्येक कंपनी के दोपहिया वाहन) वाहन न रखने के मनमाने और अहंकारी फैसले से शहर और जिले के उप-डीलरों में आक्रोश और असंतोष फैल गया है। चैत्र के पवित्र महीने में जब ग्राहकों की मांग बढ़ जाती है और चार पहिया वाहनों के साथ-साथ दोपहिया वाहनों की भी खरीद शुरू हो जाती है, तब आरटीओ के इस मनमाने और अहंकारी फैसले के कारण ग्राहकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शोरूमों में रखे वाहन ग्राहकों को उनकी पसंद के रंग, मॉडल और कंपनी चुनने की सुविधा देने के लिए ही रखे जाते हैं। अब जब ग्राहकों के लिए शोरूमों में दोपहिया वाहन उपलब्ध ही नहीं हैं, तो वे अपनी पसंद का वाहन कैसे खरीदेंगे? फिर सवाल यह उठता है कि जब अन्य वस्तुएं ग्राहकों के लिए प्रदर्शित की जाती हैं और डीलर या उप-डीलर बहुउद्देशीय वाहन भी शोरूमों में रखते हैं, जिन्हें ग्राहक चुनकर खरीद सकते हैं, तो इसमें किसी भी कानून या आरटीओ नियमों का उल्लंघन नहीं होता है। यानी, शोरूम संचालक सरकार को गुमराह करने या सरकारी खजाने को कोई वित्तीय नुकसान पहुंचाने का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इस आम और स्पष्ट बात को जानते हुए भी, जिसमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता, सूरत आरटीओ अधिकारियों ने मनमाने ढंग से मनगढ़ंत कानून जारी कर बहुउद्देशीय वाहनों के डीलरों/उप-डीलरों को निर्देश दिया है कि वे शोरूमों में वाहनों का स्टॉक न रखें, बल्कि केवल विभिन्न वाहनों की तस्वीरों के एल्बम रखकर ही व्यापार करें। इससे पिछले आठ महीनों से शहर और जिले के 250 से 300 सब-डीलरों को भारी परेशानी हो रही है और उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचा है। लोकतांत्रिक देश में तानाशाही जैसी व्यवस्था चलाकर आरटीओ अधिकारी क्या हासिल करना चाहते हैं?

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक तंगी के ऐसे कठिन दौर में, जब लोग शाम को गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक स्थिति में अन्य व्यवसाय करने को मजबूर हैं, और बहुउद्देशीय वाहन शोरूम लाखों रुपये का निवेश करके कारोबार कर रहे हैं, ऐसे में सूरत आरटीओ का यह मनमाना और मनमानी भरा फैसला किस हद तक उचित है? इतना ही नहीं, शहर के कुछ इलाकों में 10x10 की छोटी दुकानों में खुलेआम दोपहिया वाहन बिक रहे हैं, तो क्या आरटीओ अधिकारी किसी के इशारों पर कुछ खास इलाकों में ही आदेश लागू करके दोपहिया वाहन शोरूमों को परेशान नहीं कर रहे हैं? जब यह सवाल सोचने लायक है, तो इसका जवाब सिर्फ आरटीओ ही दे सकता है।

गांधीनगर के सड़क एवं परिवहन सचिव, गांधीनगर के सड़क एवं परिवहन आयुक्त और सूरत आरटीओ को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन देने के बाद, सूरत आरटीओ ने 18/12/2025 के अपने पत्र में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 33 से 43 का उल्लंघन होना सत्य नहीं है। वास्तव में, आरटीओ अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन कर रहा है और शोरूम मालिकों को मनगढ़ंत कानून दिखाकर परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है।

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गुजरात वार्षिक अधिवेशन और 'गुजरात@1$ ट्रिलियन इकोनॉमी' विषय पर सम्मेलन का आयोजन

गुजरात वैश्विक निवेशकों के लिए सर्वोत्तम डेस्टिनेशन बन गया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित गुजरात वार्षिक अधिवेशन और और 'गुजरात@1$ ट्रिलियन इकोनॉमी' विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बनाई गई विकास की राह पर चलकर गुजरात 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार उद्योगकारों के साथ खड़े रहकर तमाम आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अतीत को याद करते हुए कहा कि एक समय था, जब गुजरात में विकास केवल वापी-वडोदरा बेल्ट तक ही सीमित था। लेकिन, प्रधानमंत्री ने पूरे गुजरात के सर्वग्राही विकास की सोच के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात समिट के चलते आज गुजरात वैश्विक निवेशकों के लिए सर्वोत्तम गंतव्य (डेस्टिनेशन) बन गया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास के कारण ही आज भारत और विशेषकर गुजरात में सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक इंडस्ट्री आई है। जो काम दशकों तक असंभव प्रतीत होता था, वह आज गुजरात की धरती पर साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात की आर्थिक क्षमता का जिक्र करते हुए गर्व से कहा कि देश की केवल 5 फीसदी आबादी होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गुजारत की हिस्सेदारी 8 फीसदी है, जिसे हमें 10 फीसदी से ऊपर ले जाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश के कुल उत्पादन में गुजरात की हिस्सेदारी 17 फीसदी है जबकि देश के कुल निर्यात में गुजरात 33 फीसदी के योगदान के साथ शीर्ष पर है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2001-02 में जिस एमएसएमई की संख्या 1.85 लाख थी, वह आज बढ़कर 27.9 लाख तक पहुंच गई है। वहीं, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें, तो देश के कुल कार्गो हैंडलिंग का 40 फीसदी हिस्सा अकेला गुजरात संभालता है। इसी प्रकार, क्षेत्रवार गुजरात की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि केमिकल उद्योग में 33 फीसदी, फार्मा एक्सपोर्ट में 19.2 फीसदी और डायमंड एक्सपोर्ट में 80 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश में सबसे आगे है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गुजरात एक 'पॉलिसी ड्रिवेन स्टेट' यानी नीति-संचालित राज्य है। उद्योगकारों को उद्योग की स्थापना से लेकर संचालन तक के प्रत्येक चरण में क्लैरिटी यानी स्पष्टता मिले, इसके लिए स्पष्ट नीतियां बनाई गई हैं और समय की मांग के अनुसार इसमें आवश्यक बदलाव भी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात ने 2047 तक के 'विकसित भारत' का रोडमैप तैयार कर लिया है और उसे धरातल पर उतारने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

औद्योगिक शक्ति से वैश्विक आर्थिक केंद्र बनने की ओर गुजरात के दृढ़ संकल्प पर आधारित इस कार्यक्रम में सीआईआई के वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन श्री प्रेमराज कश्यप, वाइस चेयरमैन श्री अचल बकेरी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरशरण सिंह सहित सीआईआई के पदाधिकारी और उद्योग जगत के अग्रणी मौजूद रहे।

सूरतः पूर्व विधायक-सांसद अमरसिंह जिनाभाई चौधरी ने सरकारी और अन्य लोगों की जमीनें अवैध रूप से बेचीं, जमीन हड़पने के मामले में कार्रवाई जरूरी है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। दक्षिण गुजरात के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद अमरसिंह जिनाभाई चौधरी तापी जिले के व्यारा जिले में गणेशजी मंदिर के पास शक्ति नगर बोथेल कॉलोनी में रहते हैं। वे पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं। सरकार विधायकों और सांसदों को आजीविका के लिए व्यवसाय करने हेतु सरकारी जमीनें देती थी। अमरसिंह जिनाभाई चौधरी को भी सूरत में पूना कुम्भरिया रोड पर सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। इसी दौरान उन्हें सूरत शहर को गैस आपूर्ति करने का जिम्मा सौंपा गया और उन्होंने एक गैस एजेंसी भी शुरू की। लेकिन सूरत शहर के तेजी से विकास और कपड़ा बाजारों के निर्माण के कारण जमीन की कीमतें बढ़ गईं और चूंकि यह सड़क से लगी जमीन थी, इसलिए अमरसिंह भाई ने जमीन बेच दी। साथ ही, विधायक और सांसद होने के नाते उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और दूसरों की जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी

जमीन बेचकर मुनाफा कमाया और दूसरे व्यक्ति को दस्तावेज देकर उसे अपनी जमीन बताया। उन्होंने अपनी जमीन के आसपास की जमीन को पेट्रोल पंप चलाने के लिए बेच दिया और उससे लगी हुई जमीन, जिसे अब अंबर हाउस के नाम से जाना जाता है, भी बेच दी। उन्होंने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उस जमीन पर कब्जा किया और उसे बेच दिया। इस प्रकार, अमर सिंह जिनाभाई चौधरी ने किसी अन्य व्यक्ति की वैध भूमि पर धन के लालच में लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। सरकार द्वारा व्यापार और रोजगार के लिए दी गई भूमि को भला कैसे बेचा जा सकता है? और किसी विधायक या सांसद के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करना और अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके उसे बेचना उचित नहीं है। यदि कोई आम आदमी किसी अन्य व्यक्ति के घर और जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो सरकारी व्यवस्था उसके खिलाफ भूमि हड़पने का मामला दर्ज करने में संकोच नहीं करती। स्थानीय प्रशासन ने पाया है कि अमरसिंहभाई जिनाभाई चौधरी ने अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किया है। और यह जानते हुए भी कि भूमि को अवैध रूप से अंबर हाउस को बेचा गया था, सरकारी प्रशासन ने अमरसिंह जिनाभाई चौधरी के खिलाफ भूमि हड़पने का मामला दर्ज नहीं किया है नवसर्जन संस्कृति 2 5

सामान्य तौर पर, सरकार को आरक्षित श्रेणी के सांसदों और विधायकों के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और विधायक या सांसद से सरकार द्वारा प्राप्त पेंशन भत्ते को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा 15317 रुपये और चांदी वायदा 36502 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा में 263 रुपये का ऊछाल

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 13 से 19 मार्च के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 4003907.95 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 355217.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3648685.31 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 36981 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 61607.49 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 226392.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 160251 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 160673 रुपये के उच्च और 141121 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 160271 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 15317 रुपये या 9.56 फीसदी लुढ़ककर 144954 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 12738 रुपये या 9.7 फीसदी औंधकर 118538 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 1638 रुपये या 9.93 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 14852 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 160411 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 160749 रुपये के उच्च और 141089 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 15350 रुपये या 9.57 फीसदी लुढ़ककर 145017 रुपये प्रति 10 ग्राम बंद हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 161979 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 161979 रुपये के उच्च और 141116 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 161359 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 15907 रुपये या 9.86 फीसदी की गिरावट के साथ 145452 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 266001 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में

कमोडिटी वायदाओं में 355217 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3648685 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 226392 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36981 पॉइंट के स्तर पर

ऊपर में 269186 रुपये और नीचे में 214212 रुपये पर पहुंचकर, 267962 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 36502 रुपये या 13.62 फीसदी लुढ़ककर 231460 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 36840 रुपये या 13.46 फीसदी गिरकर 236774 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 36741 रुपये या 13.42 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 236979 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 29178.75 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा सप्ताह के अंत म ं 90.35 रुपये या 7.51 फीसदी औंधकर 1111.95 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मार्च वायदा 18.75 रुपये या 5.76 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 306.60 रुपये प्रति किलो बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 19.5 रुपये या 5.57 फीसदी घटकर 330.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा मार्च वायदा 2 रुपये या 1.06 फीसदी घटकर सप्ताह के अंत में 186.25 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 99604.66 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स इलेक्ट्रिसिटी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति एमडबल्यूएच 4980 रुपये के भाव से खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 5203 के उच्च और 4275 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 480 रुपये या 10.05 फीसदी की गिरावट के साथ 4294 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 8830 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 9421 रुपये और नीचे में 8501 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 263 रुपये या 3.01 फीसदी की तेजी के संग 8998 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 264 रुपये या 3.02 फीसदी की बढ़त के साथ 8999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 300.4 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 307.90 रुपये और नीचे में 271.4 रुपये पर पहुंचकर, 297.6 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2.10 रुपये या 0.71 फीसदी गिरकर 295.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 2.20 रुपये या 0.74 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 295.40 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 990 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 21.20 रुपये या 2.13 फीसदी औंधकर 972.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कॉटन मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 760 रुपये या 2.95 फीसदी के ऊछाल के साथ 26520 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इलायची मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति किलोग्राम 2521 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 101 रुपये या 4.00 फीसदी की नरमी के साथ 2424 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 140514.63 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 85877.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 21370.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4822.79 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 147.39 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2781.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी वायदाओं में 211.04 करोड़ रुपये, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 74317.08 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 25076.53 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 28.68 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 10.22 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इलायची वायदा में 3.10 करोड़ रुपये के ट्रेड हुए।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 6441 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35386 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 11964 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 162971 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 25574 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6312 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 15970 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 57448 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19025 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12661 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 39270 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 39630 के उच्च और 36400 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 3117 पॉइंट घटकर 36981 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशन में गुजरात में एलपीजी का पर्याप्त भंडार, अब कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं

राज्य में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध : व्हॉट्सएप, मिस्डकॉल, एसएमएस, ऑनलाइन बुकिंग तथा स्मार्टफोन ऐप से होगी बुकिंग

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य सरकार के कहे अनुसार राज्य में रसोई गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। गैस एजेंसियों की ओर से एलपीजी सिलेंडर की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक देखरेख रखी जा रही है और नागरिकों को उनके सिलेंडर के लिए एजेंसी पर जाकर कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा नागरिकों को उनके घर पर ही सरलता से सिलेंडर उपलब्ध हो; इसके लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

नागरिकों को मोबाइल के एक क्लिक से ही सिलेंडर मिले; इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा सभी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। एलपीजी बुकिंग तथा रीफिल के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और पंजीकृत लाभार्थी व्हॉट्सएप, मिस्डकॉल, एसएमएस/आईवीआर बुकिंग, स्मार्टफोन एप्लिकेशन तथा कंपनी के अधिकृत पोर्टल का उपयोग करके आसानी से बुकिंग करवा सकते हैं।

आईओसीएल की बुकिंग सुविधाएँ

आईओसीएल के अनुसार मोबाइल द्वारा एलपीजी बुकिंग के लिए निम्नानुसार सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। बुकिंग के बाद सरलता से सिलेंडर की होम डिलीवरी हो जाएगी।

व्हॉट्सएप के लिए : 7588888824
एसएमएस / आईवीआरएस : 7718955555
मोबाइल ऐप : IndianOil ONE
ऑनलाइन पोर्टल : https://cx.indianoil.in

एचपी गैस की बुकिंग के लिए निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं

व्हॉट्सएप के लिए : 9222201122
रजिस्टर्ड नंबर द्वारा कॉल से बुकिंग के लिए : 9493602222
SMS / IVRS बुकिंग के लिए: 8888823456
मोबाइल ऐप : HP PAY
ऑनलाइन पोर्टल : https://myhpgas.in

भारत गैस द्वारा आसान बुकिंग सुविधाएँ

व्हॉट्सएप के लिए : 1800224344
रजिस्टर्ड नंबर द्वारा कॉल से बुकिंग के लिए : 7710955555
SMS / IVRS बुकिंग के लिए : 7715012345
मोबाइल ऐप : HelloBPCL
ऑनलाइन पोर्टल : my.ebharatgas.com

इसके अलावा; पार्टनर वॉलेट तथा बैंकिंग ऐप की मदद से भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई जा सकती है। इन सभी बुकिंग्स में सुव्यवस्थित डिजिटल सिस्टम का अनुकरण किया जाता है और एसएमएस द्वारा उपभोक्ता को कन्फर्मेशन भेजा जाता है। घरेलू गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के साथ डिलीवरी दी जाती है। राज्य में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और बफर स्टॉक में भी निरंतर वृद्धि हो रही होने के कारण किसी भी नागरिक के लिए सरलता से घर बैठे ही डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।

समय पर डिलीवरी मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है : उपभोक्ता

खेडा जिले में ठासरा के निवासी महिपालसिंह प्रतापसिंह परमार ने कहा कि इंडेन गैस के सिलेंडर नियमित रूप से मिल रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार उनकी सर्विस अच्छी है और किसी भी प्रकार की तकलीफ के बिना समय पर डिलीवरी दी जाती है। अन्य एक उपभोक्ता परेशभाई वोरा ने कहा कि हाल में सर्विस में कोई समस्या नहीं है। बुकिंग कराने के बाद समय पर सिलेंडर मिल जाता है। कालसर गाँव के नाजिमखान नबीखान पठान ने कहा कि उन्हें आसानी से सिलेंडर मिल जाता है और वैध तरीके से डिलीवरी हो रही है। मोडासा में खुशी एचपी गैस एजेंसी के संचालक श्री हरिश्चंद्र भाटी ने कहा कि सरकार की ओर से पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रतिदिन गाड़ियाँ स्टॉक लेकर आती हैं। उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड नंबर से बुकिंग करा सकते हैं और दो दिन में उन्हें डिलीवरी मिल जाएगी। इस स्थिति में किसी को अफवाहों से पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

एलपीजी वितरण की कड़ी निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

राज्य की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तथा निजी गैस एजेंसियों में कड़ी निगरानी तथा मॉनिटरिंग के लिए राजस्व एवं पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को समय पर एलपीजी आपूर्ति मिले और अनियमितता को रोका जा सके।

एलपीजी के लिए हेल्पलाइन नंबर

राज्य में एलपीजी संबंधी किसी भी समस्या के लिए नागरिकों से राज्य हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222 पर संपर्क करने को कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों को अधिकृत रूप से सटीक जानकारी मिलती रहे।

मीठी ईद का महत्व: रमज़ान के बाद खुशियों, कृतज्ञता और रिश्तों में मिठास का त्योहार

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। रमज़ान का महीना रोज़े का पवित्र महीना है। इस त्योहार, ईद पर, दुनिया भर के मुसलमान प्रार्थना करने, भोजन बाँटने और खुशी व सद्भाव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईद-उल-फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है? ईद के उत्सव का क्या महत्व है और इसका क्या अर्थ है? इसे "मीठी ईद" क्यों कहा जाता है? ईद-उल-फितर को अक्सर "मीठी ईद" कहा जाता है। यह नाम रोज़े के महीने के अंत का जश्न मनाने के लिए मीठे पकवान बनाने और खाने की परंपरा से आया है। रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक रोज़ा रखने के बाद, परिवार सेवया (सेवया खीर), खीर, शीर खुरमा और कई तरह की मिठाइयों का आनंद लेते हैं। यह खुशी, कृतज्ञता और आत्म-अनुशासन के बाद जीवन की मिठास का प्रतीक है। यह रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और सामाजिक संबंधों को मधुर और मजबूत बनाता है। ईद के शुभ अवसर पर, दक्षिण गुजरात विकास उपभोक्ता संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, छगनलाल मेवाड़ा, पूरे मुस्लिम समुदाय को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं और अल्लाह सर्वशक्तिमान से सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

नायलॉन यार्न पर ड्यूटी से सूरत में मचा घमासान, बुनकरों ने फैसले पर उठाए गंभीर सवाल

सूरत। देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब सूरत में **(जीएनएस)**। नायलॉन यार्न पर प्रस्तावित एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लेकर उद्योग जगत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। डीजीटीआर के हालिया प्रस्ताव में चीन और वियतनाम से आयातित नायलॉन यार्न पर 23.5 रुपये से 78 रुपये प्रति किलो तक ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है, जिसके बाद से स्थानीय बुनकरों और उद्योग संगठनों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। सूरत के वीवर्स का कहना है कि यह निर्णय उनके हितों के खिलाफ है और इससे पूरे टेक्सटाइल उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि इस ड्यूटी के लागू होने से कच्चे माल की लागत बढ़ेगी, जिससे उत्पादन महंगा हो जाएगा और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है। बुनकरों के अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उद्योग पहले से ही मांग में गिरावट और लागत के दबाव से जूझ रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों का आरोप है कि स्पिनर्स द्वारा डीजीटीआर में गलत आधार पर याचिका दायर की गई थी। स्पिनर्स ने दावा किया था कि सस्ते आयात के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, जबकि वीवर्स का कहना है कि वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उनके अनुसार, कई स्पिनिंग कंपनियों ने पिछले वर्ष 600 प्रतिशत तक का मुनाफा कमाया है, जबकि कुछ कंपनियों का लाभ 132 प्रतिशत से भी अधिक रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब स्पिनर्स पहले से ही लाभ में हैं, तो एंटी-डंपिंग ड्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी। वीवर्स ने यह भी बताया कि नायलॉन FDY और मदर यार्न की मांग में पहले ही भारी गिरावट देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार, मासिक मांग में 7000 टन से अधिक की कमी आई है। ऐसे में यदि ड्यूटी लागू होती है, तो इससे उत्पादन और मांग के बीच असंतुलन और बढ़ सकता है, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के बुनकरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर उद्योग संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। साथ ही, सांसद सी.आर. पाटिल को भी ज्ञापन सौंपकर ड्यूटी लागू न करने की मांग की जाएगी। बुनकरों का कहना है कि यह केवल एक औद्योगिक मुद्दा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा मामला है। उद्योग नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीजीटीआर की सिफारिश अंतिम निर्णय नहीं है। अब अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को लेना है, जिसके लिए 90 दिनों की समयसीमा निर्धारित है। ऐसे में वीवर्स ने उद्योग से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी तरह की जल्दबाजी में नायलॉन यार्न की खरीद न करें और स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करें। इस पूरे विवाद के बीच वर्ष 2018 का उदाहरण भी सामने लाया जा रहा है, जब डीजीटीआर ने इसी तरह की एंटी-डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की थी, लेकिन अंतिम निर्णय में सरकार ने बुनकरों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इससे उद्योग को उम्मीद है कि इस बार भी उनकी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सचिव मयूर गोलवाला, सूरत नायलॉन वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मयूर चेवली और वेडरोड वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्रभाई चाहवाला ने संयुक्त रूप से कहा कि वे उद्योग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उनका कहना है कि यदि यह ड्यूटी लागू होती है, तो इससे सूरत के टेक्सटाइल सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा और रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल, इस मुद्दे पर पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की नजर केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। यह निर्णय न केवल सूरत, बल्कि देशभर के टेक्सटाइल उद्योग की दिशा और भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

जंक फूड की मार: मासूमों की सांसों तक पहुंचा खतरा, राजकोट में तीन बच्चों को मिला नया जीवन

(जीएनएस)। राजकोट। बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों ने अब सबसे संवेदनशील वर्ग—छोटे बच्चों—की सेहत पर गंभीर असर डालना शुरू कर दिया है। जंक और पैकेट फूड का बढ़ता चलन बच्चों के लिए धीमा जहर साबित हो रहा है, जिसका एक चिंताजनक उदाहरण मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल राजकोट में सामने आया, जहां दो से ढाई साल के तीन मासूम बच्चों—अवनी, अमित और पृथ्वीराज—को समय रहते इलाज देकर नया जीवन दिया गया। इन तीनों बच्चों को बार-बार संक्रमण की शिकायत के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि संक्रमण केवल सामान्य नहीं था, बल्कि यह बढ़कर फेफड़ों तक पहुंच चुका था। स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि तत्काल सर्जिकल हस्तक्षेप के बिना बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो सकता था। यह मामला इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गलत खानपान का असर बच्चों के शरीर पर कितनी तेजी से और कितनी गहराई तक पड़ सकता है।

शिशु सर्जन डॉ. जयदीप गणात्रा के अनुसार, तीनों बच्चे गंभीर निमोनिया से पीड़ित थे। दो बच्चों का इलाज आधुनिक तकनीक 'थोराकोस्कोपी' के माध्यम से किया गया, जिसमें छाती के भीतर जमे खून के थक्कों को बिना बड़ा चीरा लगाए हटाया गया।

वहीं, अवनी की स्थिति अधिक गंभीर होने के कारण उसके फेफड़े के प्रभावित हिस्से को हटाने के लिए 'लोबेक्टॉमी' जैसी जटिल सर्जरी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है और इसमें डॉक्टरों की विशेषज्ञता और अनुभव की बड़ी भूमिका होती है।

डॉ. गणात्रा ने बताया कि थोराकोस्कोपी एक अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीक है, जिसमें छोटे-छोटे छेद के जरिए कैमरा और उपकरण डालकर शरीर के अंदर की समस्या का समाधान किया जाता है। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें मरीज को कम दर्द होता है, रिकवरी तेजी से होती है और अस्पताल में भर्ती रहने का समय भी कम हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की यह उपलब्धि ऐसे जटिल मामलों में बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है।

सफल इलाज के बाद तीनों बच्चे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जीते हुए खेल-कूद में व्यस्त हैं। इस सफलता के पीछे केवल एक डॉक्टर नहीं, बल्कि पूरी टीम का सामूहिक प्रयास रहा। शिशु शल्य चिकित्सा विभाग की डॉ. ख्याति जेठवा, रेजिडेंट डॉक्टरों की टीम, ऑपरेशन थियेटर इंचार्ज दयाबेन गजेरा, सहायक पूजा वाडोलिया सहित अन्य स्टाफ ने मिलकर इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफल बनाया।

हालांकि इस घटना ने एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया है—क्या हम अपने बच्चों के खानपान को लेकर पर्याप्त सजग हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल बच्चों में जंक फूड, पैकेट स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। इन खाद्य पदार्थों में पोषण तत्वों की कमी होती है, जबकि नमक, चीनी और हानिकारक फैट की मात्रा अधिक होती है। इसका सीधा असर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है, जिससे वे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं।

डॉ. गणात्रा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को जंक और पैकेट फूड से जितना संभव हो दूर रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों के आहार में घर का ताजा और संतुलित भोजन शामिल होना चाहिए, जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, दूध और फल। यही भोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि बचपन से ही सही खानपान की आदतें विकसित की जाएं, तो कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है।

इस मामले ने यह भी दिखाया कि सही समय पर पहचान और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल राजकोट का शिशु शल्य चिकित्सा विभाग नवजात और छोटे बच्चों में जटिल सर्जिकल समस्याओं के उपचार में विशेषज्ञता रखता है। यहां एसोफैजियल एट्रेसिया, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन, डायाफ्रामिक हर्निया, आंतों में रुकावट, हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिसाइटिस और नवजात सर्जरी जैसे मामलों का इलाज एनआईसीयू के सहयोग से सफलतापूर्वक किया जाता है। आज के दौर में जब सुविधा और स्वाद के नाम पर जंक फूड हर घर में आसानी से उपलब्ध है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि अभिभावक जागरूक रहें और बच्चों के खानपान पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी बच्चों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। राजकोट की यह घटना न केवल एक सफल चिकित्सा कहानी है, बल्कि एक चेतावनी भी है—कि यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो जंक फूड बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है।

कचरे में फेंके गए आयुष्मान कार्डों ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की परतें, सूरत-अंकलेश्वर कनेक्शन से उठे गंभीर सवाल

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के अंकलेश्वर में कचरे के ढेर से बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड मिलने की घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, बल्कि संभावित रूप से एक बड़े सिस्टम फेलियर या संगठित गड़बड़ी का संकेत देता है। खास बात यह है कि कचरे में मिले कई कार्ड सूरत के लाभार्थियों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे इस पूरे मामले का दायरा और भी व्यापक हो गया है।

घटना अंकलेश्वर के अंसार मार्केट इलाके की है, जहां अचानक कचरे के बीच हजारों की संख्या में आयुष्मान कार्ड पड़े हुए मिले। स्थानीय लोगों ने जब इन कार्डों को देखा, तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो गया। सवाल उठने लगे कि जिन कार्डों के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज का अधिकार मिलता है, वे आखिर कचरे में कैसे पहुंच गए। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉ. सुशांत कोठालावाला के निर्देश पर एक टीम मौके पर भेजी गई। टीम ने वहां से बड़ी संख्या में कार्ड जब्त किए और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि इन कार्डों में कई ऐसे नाम और विवरण मौजूद हैं, जो सूरत के लाभार्थियों से जुड़े हो सकते हैं। इससे यह आशंका और गहरा गई कि मामला केवल स्थानीय स्तर का नहीं है, बल्कि इसमें किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका हो सकती है।

आयुष्मान कार्ड, जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना के तहत जारी किए जाते हैं, गरीब और वंचित वर्ग के लिए जीवन रक्षक साबित होते हैं। इन कार्डों के माध्यम से लाभार्थियों को विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त या बेहद सस्ती चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं। ऐसे में इन कार्डों का इस तरह कचरे में मिलना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि कहीं न कहीं इस योजना के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं।

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह घटना एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं किसी अस्पताल, एजेंसी या दलाल नेटवर्क ने इन कार्डों का दुरुपयोग किया हो और बाद में सबूत मिटाने के लिए इन्हें कचरे में फेंक दिया गया हो। यदि ऐसा है, तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि गरीबों के अधिकारों के साथ भी बड़ा अन्याय है।

यह भी गौर करने वाली बात है कि भरूच और सूरत जिलों में पहले भी आयुष्मान कार्ड के दुरुपयोग के मामले सामने आ चुके हैं। कई बार यह आरोप लगे हैं कि कुछ अस्पतालों ने फर्जी मरीज दिखाकर या अनावश्यक इलाज के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। ऐसे में अंकलेश्वर की यह घटना इन पुराने मामलों को फिर से चर्चा में ले आई है और जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के कई पहलुओं पर काम शुरू कर दिया है। कार्डों में मौजूद डेटा के आधार पर उनकी उत्पत्ति, वितरण और संभावित उपयोग की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये कार्ड किन-किन लोगों के नाम पर जारी किए गए थे और क्या वे वास्तव में लाभार्थी हैं या नहीं।

इस घटना के बाद आम जनता के बीच भी चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, यदि इस तरह की लापरवाहियों और गड़बड़ियों का शिकार हो रही है, तो इसका सीधा असर आम लोगों के भरोसे पर पड़ता है। लोगों ने मांग की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल व्यक्तिगत लापरवाही का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करती हैं। यदि डेटा प्रबंधन, वितरण प्रक्रिया और निगरानी तंत्र मजबूत हो, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और संबंधित विभाग तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर सुधार करें और पारदर्शिता को बढ़ावा दें।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सही क्रियान्वयन और निगरानी भी उतनी ही जरूरी है। आयुष्मान योजना जैसी पहलें तभी सफल हो सकती हैं, जब उनमें शामिल हर स्तर पर जिम्मेदारी और ईमानदारी हो।

फिलहाल, जांच जारी है और सभी की नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर इन कार्डों के कचरे में मिलने के पीछे की असली वजह क्या है। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष इस मामले की सच्चाई को सामने लाएंगे। लेकिन तब तक यह घटना एक चेतावनी के रूप में सामने है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो ऐसी योजनाएं अपने उद्देश्य से भटक सकती हैं और जिन लोगों के लिए बनाई गई हैं, वही इससे वंचित रह सकते हैं।

डिजिटल जनगणना से बदलेगा सूरत का भविष्य, 18 लाख संपत्तियों का होगा स्मार्ट सर्वे

(जीएनएस)। सूरत। देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शामिल सूरत अब 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक शहर में व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा। इस बार जनगणना पारंपरिक तरीके से अलग, आधुनिक तकनीक के जरिए की जाएगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि डेटा की सटीकता और उपयोगिता भी बढ़ेगी। इस डिजिटल जनगणना के अंतर्गत शहर की लगभग 18 लाख रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि यह सर्वे केवल आंकड़े जुटाने का काम नहीं करेगा, बल्कि सूरत के भविष्य के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पिछले दो दशकों में सूरत की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में जहां शहर की आबादी 46.45 लाख थी, वहीं अब यह आंकड़ा करीब 90 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इस तेजी से बढ़ते जनसंख्या दबाव ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। ऐसे में यह जनगणना प्रशासन को सटीक आंकड़े उपलब्ध कराएगी, जिनके आधार पर दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

प्रशासन ने इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर मानव संसाधन की तैनाती की है। सूरत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में लगभग 12 हजार एन्यूमेरेटर और 2 हजार सुपरवाइज़र नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक एन्यूमेरेटर को 150 से 200 घरों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह कार्य पूरी तरह डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड होगा और किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि की संभावना कम होगी।

सर्वे के दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा स्तर, रोजगार की स्थिति, माइग्रेशन पैटर्न और आवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जाएंगी। यह डेटा शहर की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में मदद करेगा। साथ ही, इससे यह भी स्पष्ट होगा कि किन क्षेत्रों में अधिक विकास की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

डिजिटल प्रक्रिया का एक बड़ा लाभ यह भी है कि प्रशासन को रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा। इससे योजना निर्माण की प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो वहां समय रहते नई सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और जल आपूर्ति योजनाओं को लागू किया जा सकेगा।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें डिजिटल उपकरणों के उपयोग, डेटा एंट्री और सर्वर अपलोड की पूरी प्रक्रिया सिखाई जा रही है, ताकि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। इसके अलावा, सरकार ने इस कार्य में लगे कर्मचारियों को करीब 20 हजार रुपये का मेहनताना देने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और वे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम दें।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डिजिटल जनगणना न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि शहर के समग्र विकास के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करेगी। सटीक और अद्यतन डेटा के आधार पर ही स्मार्ट सिटी, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं सफल हो सकती हैं।

कुल मिलाकर, 2027 की यह डिजिटल जनगणना सूरत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यह केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक व्यापक प्रयास है। यदि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होती है, तो सूरत आने वाले वर्षों में और भी संगठित, विकसित और स्मार्ट शहर के रूप में उभर सकता है।